

सार समाचार

यूपी : रायबरेली के भाजपा मंडल अध्यक्ष पर को जानलेवा हमला

रायबरेली (एजेंसी)। भाजपा मंडल अध्यक्ष शिव लखन राम सुमेर लोधी निवासी पूरे रामबक्स मजरे चक मलिक भिटी रात में निमंत्रण पर गए थे। वह जोहवा नटकी रेलवे क्रासिंग के पास से वापस लौट रहे थे। इस दौरान मार्ग पर दबंगों ने उन्हें रोक कर उन पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले की सूचना मिलते ही सरेनी विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ डलमऊ कोवाली पहुंच गए और दबंगों पर सख्त कार्रवाई के लिए अड़ गए। जानकारी होने पर एसडीएम जीत लाल सेनी मौके पर पहुंच गए। कार्रवाई का आश्वासन देकर विधायक और कार्यकर्ताओं को शांत कराया।

यूपी : जिस पुल का पीएम को करना है उद्घाटन, वहां सपाइयों ने फीता काट दौड़ाई बाइक

मिर्जापुर (एजेंसी)। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकार्पण से पहले ही बड़ी संख्या में सपाइयों ने जिले के चुनाव में गंगा नदी पर बने पक्का पुल पर फीता काटकर बाइक से आर-पार की यात्रा की। प्रशासन और पुलिस को इसकी कानोकान भनक तक नहीं लग पायी। खुफिया और एसपीजी को भी सपा की योजना का पता नहीं चल पाया है। पीएम के आने के पहले आयोजन को प्रभावित किया जाना कहीं न कहीं से सुरक्षा में चूक है। इसे लेकर भाजपा और अपना दल एस के नेताओं के साथ ही कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी देखी गई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जुलाई को जिले में आ रहे हैं। वह बाणसागर परियोजना,चुनार पक्का पुल का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही राजकीय मेडिकल कालेज, मिर्जापुर इलाहाबाद मार्ग का शिलान्यास भी करेंगे। इसे लेकर शैलारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। भाजपा और सहयोगी दल अपना दल एस की ओर से कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंकी गई है। देश और प्रदेश की सारी सुरक्षा एजेंसियों ने यही पर डेरा जमाया है। बावजूद इसके सपा जिलाध्यक्ष आशीष यादव की अगुवायी में बड़ी संख्या में पदाधिकारी, कार्यकर्ता चुनार में गंगा नदी पर बने पक्का पुल पर पहुंच गए। उन्होंने वहां पहुंचकर पुल पर फीता बांधकर काटा और बाइक से पुल को आर पार करके लौट आए। सपा नेताओं ने कहाकि यह पुल उनकी सरकार के कार्यकाल है। ऐसे में उसके लोकार्पण का अधिकार उनको है। इसलिए उनलोगों ने लोकार्पण कर दिया। सपाइयों के आने के बाद तक प्रशासन को पता नहीं चला। जब सोशल मीडिया पर सपाइयों के आयोजन का वीडियो वायरल हुआ और भाजपा व अपना दल एस के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने इसे देखकर नेताओं तक पहुंचा तब खलबली मची। भाजपा के नेताओं ने डीएम और एसपी से इस बारे में पूछताछ की गई तो बताया गया कि कोई लोकार्पण नहीं हुआ है। पुल बना ही लोगों के आवागमन के लिए है तो उस पर आना जाना कोई लोकार्पण नहीं है। फिर भी भाजपा के नेताओं ने कहाकि सपाइयों को ऐसा करने से रोकना तो चाहिए था। पुल पर फीता काटकर यात्रा करने वालों में पूर्व विधायक जगतबा पटेल, देवी प्रसाद चौधरी,संतोष यादव, बच्चा बाबू यादव, रामलखन यादव, सुरेश यादव, सूर्यबली यादव, रोहित शुक्ला, सुनील कुमार पाण्डेय, अभय यादव, उपेन्द्र तिवारी, नितेश तिवारी, रविन्द्र कुमार, सुशील कुमार पाण्डेय,आशीष दुबे, गुलाम मुस्तफा I, विक्रान्त उपाध्याय, परवेज भाई,रविशंकर, अब्दुल खालिद, ध्यानचंद, स्वामीशरण दुबे, सुनील सिंह पटेल आदि रहे।

बदमाशों ने खिड़की से हाथ डालकर ट्रेन में बैठी महिलाओं से छीने बैग-जेवर, हुए फार

शाहजहांपुर (एजेंसी)। शाहजहांपुर में गुरुवार रात डेढ़ बजे गरी और रेलवे क्रासिंग संख्या 227 के बीच बदमाशों ने लखनऊ-चंडीगढ़ एक्सप्रेस को निशाना बनाया। पहले से सवार बदमाश ने चेन खींचकर ट्रेन को रोक लिया। गाड़ी के रुकते ही झाड़ियों से निकले बदमाशों ने खिड़की से हाथ डाल कर स्लीपर कोच में बैठी महिलाओं के बैग व जेवर लूट लिए और फार हो गए। बस कंडक्टर से सात लाख का इनामी बने मुन्ना बजरंगी पर बनेगी फिल्टर पीडिडों ने मुरादाबाद जीआरपी पर तहरीर दी है। आईजी जीआरपी ने शुक्रवार को घटनास्थल का निरीक्षण किया। लखनऊ से चलकर चंडीगढ़ जाने वाले 12232 लखनऊ-चंडीगढ़ एक्सप्रेस गुरुवार रात 1.11 बजे शाहजहांपुर से बरेली दिशा की ओर रवाना हुई थी।

दैनिक

क्रांति समय

»»» तीन दिन तक स्कूल में रोजाना 45 मिनट तक रोका, गेट पर जड़ा ताला

अब शिक्षकों को बनाया बंधक, मांगा था वेतन

नई दिल्ली (एजेंसी)। राजधानी में स्कूल में बच्चों को बंधक बनाए जाने का मामला अभी शांत नहीं हुआ है कि अब एक स्कूल द्वारा शिक्षकों को बंधक बनाने का मामला प्रकाश में आया है।

गुरु हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल के शिक्षक बीते दिनों से स्कूल में अपने वेतन मांग कर रहे हैं। इन्हें दो महीने से वेतन नहीं मिला है। उनका आरोप है कि 10 से 12 जुलाई तक रोजाना स्कूल खत्म होने के बाद 45 मिनट तक उन्हें रोककर रखा गया। इस दौरान स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया गया। इससे खफा शिक्षकों ने हंगामा कर हड़ताल कर

दी। शिक्षकों ने पुलिस, महिला आयोग व शिक्षा निदेशालय से इस मामले में शिकायत की है।

स्कूल स्टाफ एसोसिएशन ने उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से भी शिकायत की है। स्कूल की स्टाफ एसोसिएशन ने महिला आयोग, शिक्षा निदेशालय व पुलिस को जो शिकायत दी है। उसमें स्कूल में जुतन मांगने पर स्कूल द्वारा 10 से 12 जुलाई तक रोजाना दोपहर 1.30 बजे से 2.15 बजे तक स्कूल के गेट बंद कर दिए गए और उनको बाहर नहीं जाने दिया गया। कारण यह है कि शिक्षक स्कूल प्रबंधन से बीते

दो महीने का वेतन मांग रहे हैं, जो अभी तक नहीं दिया गया। हम लोगों ने पहले भी शिक्षा निदेशालय व उपमुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया से शिकायत की थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्कूल प्रबंधन द्वारा तीन दिनों तक आदेश दिया गया है कि स्कूल का गेट बंद कर दिया जाए। लिहाजा हमने पुलिस को 100 नंबर पर सूचना दी। इस दौरान आये एक पुलिसकर्मी ने गेट कीपर का लिखित बयान भी नहीं लिया। लिहाजा दिल्ली पुलिस से अनुरोध किया गया है कि इस मामले में एफआईआर की जाए। स्कूल के 139 स्टाफ ने

उपमुख्यमंत्री, पुलिस, महिला आयोग से की शिकायतगुरु हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल का मामला

लिखित हस्ताक्षरयुक्त पत्र दिया है। वेतन न दिये जाने के मुद्दे पर बुहस्पतिवार को शिक्षक पूरे दिन हड़ताल पर रहे।

पहले शिक्षक स्कूल के बाहर बैठे रहे, उसके बाद शिक्षक स्कूल के स्कूल परिसर में धरनारत रहे। उधर स्कूल प्रबंधन के पूर्व चेयरमैन व डीजीएसएमसी के सदस्य कुलवंत सिंह का कहना है कि बंधक बनाने का शिक्षकों का आरोप गलत है। शिक्षा निदेशालय का एक आदेश है जिसके तहत

स्कूल बंद होने के बाद कुछ समय तक शिक्षकों को रहना होता है, ताकि बचा हुआ काम कर लें।

इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से स्कूल गेट बंद रहते हैं। उन्होंने कहा कि हमने शिक्षकों को कहा थ कि शनिवार को काम कर लें, जिससे उन्हें स्कूल के बाद रुकना नहीं पड़ेगा, लेकिन शिक्षक नहीं माने।

श्री सिंह ने कहा कि जहां तक सैलरी का मामला है, स्कूल में फंड की कमी है, जिसके चलते बीते सात आठ महीने से देर से वेतन दिया जा रहा है।

सोनम मर्डर केस:

गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने वाले तीनों डॉक्टरों को सजा

लखीमपुर-खीरी (एजेंसी)। साल 2011 में निघासन थाने के अंदर हुए सोनम मर्डर केस में गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने के आरोपी तीन डॉक्टरों को सीजेएम कोर्ट ने शुक्रवार को सजा सुना दी। सीजेएम सुनील प्रसाद ने इन तीनों डॉक्टरों को तीन-तीन साल की कैद और दस-दस हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। 10 जून 2011 को निघासन कस्बे के अंदर थाने के अंदर 14 साल की किशोरी सोनम की लाश लटकती मिली थी। सोनम के परिवार वालों ने पुलिस वालों पर हत्या का शक जाहिर किया था। 11 जून को डॉक्टरों के पैनल ने सोनम का पोस्टमार्टम किया। जिला अस्पताल में तैनात रहे डॉ. अजय अग्रवाल, डॉ अरुण कुमार शर्मा, डॉ. एसपी सिंह ने सोनम का पोस्टमार्टम

किया था। इसमें मृत्यु का कारण हैंगिंग बताया था। इसके बाद 13 जून को लखनऊ के चार डॉक्टरों की टीम ने सोनम का दोबारा पोस्टमार्टम किया। इसमें गला चोटकर हत्या किए जाने की बात कही गई। इस रिपोर्ट के बाद शासन ने तीनों डॉक्टरों को निलंबित कर दिया। इस मामले में सीबीसीआईडी के इंस्पेक्टर हरपाल सिंह ने 12 जुलाई 2011 को जिला अस्पताल लखीमपुर के तीन डॉक्टरों पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में कुल 6 गवाहों को अदालत में पेश किया गया था। सीजेएम सुनील प्रसाद ने डॉ. अजय अग्रवाल, डॉ. अरुण कुमार शर्मा और डॉ. एसपी सिंह को तीन-तीन साल के कारावास समेत दस दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

अयोध्या मंदिर विवाद: सुप्रीम कोर्ट में बोला शिया वज़फ़बोर्ड-मस्जिद इस्लाम का हिस्सा नहीं है, बाबरी का संरक्षक शिया था

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद के सुनवाई के दौरान शिया वक्फ बोर्ड ने कहा है कि मस्जिद इस्लाम हिस्सा नहीं है। उसने कहा कि देश में शांति, सुरक्षा और एकता के लिए शिया समुदाय ने मस्जिद का मसला नहीं उठाया। शिया वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से विवाद को सुलझाना चाहते हैं। बोर्ड ने साफ कहा कि बाबरी मस्जिद का संरक्षक एक शिया था और इसलिए सुन्नी वक्फ बोर्ड या कोई और भारत में मुसलमानों के प्रतिनिधि नहीं हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। मुसलमानों और सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से पेश सीनियर ऐडवोकेट राजीव धवन ने कहा, 'बांमियान बुद्ध की मूर्तियों को मुस्लिम तालिबान ने नष्ट किया था और बाबरी मस्जिद को हिंदू तालिबान को ओर से ध्वस्त किया गया।

दिल्ली के चीफ सेकटरी के साथ कथित मारपीट का मामला

खंगाले सीएम, डिप्टी सीएम के कॉल रिकॉर्ड, चार्जशीट तैयार

नई दिल्ली ■ एजेंसी

दिल्ली के चीफ सेकटरी (सीएस) अंशु प्रकाश के साथ सीएम हाउस में हुई कथित मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस ने सीएम अरविंद केजरीवाल व डेप्युटी सीएम मनीष सिसोदिया के कॉल डीटेल तक खंगाले हैं। देश का यह पहला ऐसा मामला होगा जब किसी प्रदेश की पुलिस ने अपने ही मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री के कॉल डिटेल्स खंगाले हों।

सूत्रों का कहना है कि सीएम व डेप्युटी सीएम को साजिशकर्ता की भूमिका में रखने वाली दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की चार्जशीट तैयार कर चुकी है।

बस चंद कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करना बाकी है, जिसके बाद चार्जशीट अदालत में दायर कर दी जाएगी। सूत्र दावा कर रहे हैं कि एलजी अनिल बैजल से संवेशन के अलावा इस बात पर भी राय ली



जा रही है कि चार्जशीट दाखिल करने से पहले राष्ट्रपति से मंजूरी लेनी चाहिए या नहीं। पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार सीएस अंशु प्रकाश मामले में जो फाइनल चार्जशीट बनकर तैयार हुई है, वह लगभग 850 से 900 पेज की है। इसका रफ ड्राफ्ट करीब छह हजार पन्नों का था जिसे एडिट करके इतना बनाया गया। इस केस के लिए नियुक्त किए गए सीनियर पब्लिक प्रॉसिक्यूटर मोहित माथुर अब इस चार्जशीट

खाना नंबर 11 में केजरीवाल, सिसोदिया

पुलिस सूत्रों के अनुसार, सीएस मारपीट मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल, डेप्युटी सीएम मनीष सिसोदिया, विधायक प्रकाश जारवाल, राजेश त्रिी, त्रुनाराज, मदनलाल, अमानलुल्लाह खान, प्रवीण कुमार, अजय दत्त, दिनेश मोहनिया, संजीव झा, राजेश गुप्ता और नितिन त्यागी को आरोपी बनाया गया है। अमानलुल्लाह व प्रकाश जारवाल के खिलाफ पुलिस ने सीएस के साथ मारपीट करने व धमकी देने की धारा भी लगाई है। अन्य सभी को साजिश रचने व उसमें शामिल होने की धारा 120बी के तहत बुक किया गया है। सभी के नाम चार्जशीट के खाना नंबर 11 में रखे हैं।

सीएम के खिलाफ अहम सबूत का दावा

इस मामले में सीएम, डेप्युटी सीएम के अलावा 11 विधायकों से पूछताछ की गई है। दो विधायकों अमानलुल्लाह व प्रकाश जारवाल को मारपीट व धमकी देने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। किसी ने सीएस के साथ मारपीट करने या मारपीट होने की बात स्वीकार नहीं की है लेकिन इस मामले में जो सबसे अहम सबूत पुलिस के पास है, वे हैं मुख्यमंत्री केजरीवाल के पूर्व सलाहकार वीके जैन। मजिस्ट्रेट के सामने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराए हैं कि उनके सामने सीएस के साथ मारपीट की गई।

लखनऊ (एजेंसी)। वेतनमान और केंडर तय करने जैसी मांगों पर वाणिज्य कर विभाग को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभाग की छवि सुधारने और ट्रेड और मजदूर यूनियन जैसा व्यवहार न करने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि यूपी जैसे बड़े कंज्यूमर वाले प्रदेश में केवल 13 लाख व्यापारियों का जीएसटी में पंजीकरण और केवल 58 हजार करोड़ के राजस्व से बात नहीं बनने वाली। एक्साइज विभाग का राजस्व टारगेट वाणिज्य कर विभाग के लिए एक आईना हो सकता है। उसने अपना राजस्व टारगेट 14 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर लगभग 30 हजार करोड़ रुपये किया है। ऐसे में वाणिज्य कर विभाग भी अपना राजस्व टारगेट 58 हजार करोड़ से बढ़ाकर एक लाख 16 हजार करोड़ नहीं तो एक लाख करोड़ रुपये तो कर ही सकते हैं।

व्यापारियों को प्रताड़ित करना बंद करें

उ.प्र. वाणिज्य कर सेवा संघ के 52वें अधिवेशन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभारम्भ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वाणिज्य कर अधिकारी अपने काम और व्यवहार से अपनी छवि में सुधार लाएं। प्रदेश के दौरे पर हमें कई जनपदों में व्यापारियों को ई-वे बिल और अन्य बातों को लेकर व्यापारियों को प्रताड़ित करने की शिकायतें मिलती हैं। अधिकारी इनको



सुलझाने और सुधारने का प्रयास करें। विभागीय अधिकारी और व्यापारियों में विश्वास की परंपरा होना बहुत जरूरी है। हमारा दृष्टिकोण मानवीय हो व्यापारियों का शोषण नहीं होना चाहिए क्योंकि वह हमारा उपभोक्ता है। उसमें यह भाव पैदा कि वह कर चोरी करने के बजाए हमारी बनाई

सोनम मर्डर केस : कत्ल को बताया था आत्महत्या

गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने वाले तीन डॉक्टर दोषी करार,

लखीमपुर। साल 2011 में निघासन थाने के अंदर सोनम की हत्या हुई थी। इस घटना के बाद जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई थी। जिसमें हत्या को आत्महत्या बताया गया था। जिसके बाद इस मामले में लखनऊ की टीम ने शव का दोबारा पोस्टमार्टम किया था। इस मामले में जिला अस्पताल के डॉ. एसपी सिंह, डॉ. एके शर्मा और डॉ. एके अग्रवाल ने गलत पोस्टमार्टम किया था। सीजेएम कोर्ट में तीनों डॉक्टरों को दोषी करार दिया है। सजा का ऐलान भी जल्द ही कर दिया जाएगा।

सोनम के पहले पोस्टमार्टम पैनल में शामिल रहे डॉ. एसपी सिंह, डॉ. एके अग्रवाल और डॉ. एके शर्मा के बयान इस

मामले में अहम माने जा रहे थे। सीबीसीआईडी भी अपनी जांच का एक सिरा इन डॉक्टरों के बयानों पर टिकाए हुए था।

इन तीनों डॉक्टरों के पैनल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सोनम की मौत की वजह हैंगिंग बताई गई थी। यानी सोनम की मौत फंसी लगने से हुई है। इसके बाद लखनऊ से आई एक्सपर्ट टीम की रिपोर्ट ने कहा कि सोनम की मौत गला दबाने से हुई है। उस रिपोर्ट के बाद उन डॉक्टरों का पैनल सवालों के घेरे में था, जिन्होंने सोनम का पहली दफा पोस्टमार्टम किया था।

दिल्ली में बारिश से लोगों को राहत

नई दिल्ली (एजेंसी)। राजधानी दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में शुक्रवार को हुई बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के मुताबिक पालम में 0.4 मिलीमीटर और रिज में 8.6 मिमी बारिश दर्ज की गयी। विभाग ने दिनभर बादल छाये रहने तथा सामान्य बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली का न्यूनतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो इस मौसम के औसत से एक डिग्री सेल्सियस अधिक है। हालांकि कल के न्यूनतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस से यह कम है। राजधानी का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आस-पास रहने का अनुमान है। गुरुवार को अधिकतम तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था जो सामान्य से दो डिग्री अधिक था।

यूपी में अगले पांच दिनों तक बारिश के आसार

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ व राज्य के अधिकांश जिलों में शुक्रवार सुबह से ही रुक-रुककर बारिश हो रही है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गयी है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले पांच दिनों तक राजधानी और आसपास के जिलों में बारिश होने के आसार हैं। उग्र मौसम विभाग के निदेशक जे.पी गुप्ता के अनुसार, अधिकांश जिलों में बदली का असर रहेगा और अगले पांच दिनों तक कहीं सामान्य तो कहीं तेज बारिश होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने की संभावना है। बदली की वजह से गर्मी व उमस से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार को राजधानी लखनऊ का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। लखनऊ के अतिरिक्त शुक्रवार को गोरखपुर का न्यूनतम तापमान 22 डिग्री, कानपुर का 21 डिग्री, इलाहाबाद का 20 डिग्री, झांसी का 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

जो मनुष्य मन में उठे हुए क्रोध को दौड़ते हुए रथ के समान शीघ्र रोक लेता है, उसी को मैं सारथी समझता हूं, क्रोध के अनुसार चलने वाले को केवल लगाम रखने वाला कहा जा सकता है - गौतम बुद्ध

कांग्रेस पर जितना तीखा हमला

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पंजाब के मुकसर जिले के मलौट में किसानों को केन्द्र में रखकर कांग्रेस पर जितना तीखा हमला बोला उसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है। यानी आगामी विधानसभा चुनावों एवं लोकसभा चुनाव में भाजपा एवं सहयोगियों के लिए किसानों के लिए सरकार द्वारा किया काम बड़ा मुद्दा होगा। मोदी ने अपनी सरकार को किसान का सबसे हितैषी सरकार साबित किया तो कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने अपने शासन में किसानों का केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर इनका शोषण किया। 14 खरीफफसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने के निर्णय को मोदी, अन्य मंत्री और भाजपा के नेता बड़े कदम के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। मोदी और उनके सहयोगियों का पूरा फोकस इस बात को साबित करने पर है कि जहां कांग्रेस ने अपने शासनकाल में किसान और कृषि को तबज्जो नहीं दी और इनकी अनदेखी की वहीं उनकी सरकार ने किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, जिनसे किसान लाभान्वित होंगे। इसमें दो राय नहीं कि सरकारों ने अपने भाषणों और घोषणाओं में किसान और कृषि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता अवश्य दर्शायी लेकिन किसानों की दशा बिगड़ती गई। आज यदि कोई चाहकर किसान नहीं बना चाहता तो इसका पूरा दोष पूर्व की सरकारों पर ही जाएगा। चूंकि कांग्रेस ने सबसे लंबे समय तक शासन किया है इसलिए वह सबसे ज्यादा दोषी मानी ही जाएगी। यह भी सच है कि अभी मोदी सरकार के कदमों से कृषि के क्षेत्र में प्रत्यक्ष कोई चमत्कार नहीं दिख रहा है, पर इसने किसानों को फेकस में रखा है यह सच है। मोदी सरकार इस तरह का स्थायी तंत्र एवं मूलभूत सुविधाएं विकसित करने पर काम कर रही है, जिससे भविष्य में कृषि को मजबूत आधार मिल जाए। उदाहरण के लिए फसल बर्बाद न हो इसके लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना चल रही है। नये गोदाम और फूड पार्क बनाए जा रहे हैं। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसान को फसल नष्ट होने से नुकसान न उठाना पड़े। ग्रूरिया अब स्थायी रूप से सुलभ हो गया है। कई सिंचाई परियोजनाओं पर काम हो रहा है। मिट्टी जांच के लिए नौ हजार से अधिक प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। सरकार का दावा है कि 15 करोड़ से ज्यादा किसानों को मुदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। इस तरह ऐसे अनेक काम गिनाए जा सकते हैं, जिनसे पता चलता है कि मोदी सरकार का रवैया किसानों के संदर्भ में अलग है।

समस्या के प्रति लापरवाही

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भूजल का गिरता स्तर एक बड़ी और गंभीर समस्या में तब्दील होता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए इस समस्या के प्रति लापरवाही बरतने के लिए केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और स्थानीय निकायों को कड़ी फटकार लगाई है। शीर्ष अदालत ने इस मसले पर नीति आयोग की एक रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया गया है। वास्तव में देखा जाए तो भूजल केवल दिल्ली की समस्या नहीं रह गई है। यह राष्ट्रीय समस्या बनती जा रही है, क्योंकि देश भर में निरंतर भूजल का स्तर गिरता जा रहा है। आज से एक दशक पहले तीस मीटर की गहराई पर पानी उपलब्ध हो जाता था, मगर अब साठ-सत्तर मीटर पर पानी उपलब्ध हो रहा है। केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु भूजल की समस्या से ज्यादा प्रभावित हैं। इनमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली की हालत सबसे ज्यादा खराब है। सुप्रीम कोर्ट ने घटते भूजल की समस्या की भयावहता से संबंधित एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि दिल्ली में 2021 तक भूजल बचेगा नहीं। इसका मतलब है कि लोग यहां जिंदा नहीं रह सकते। जस्टिस मदन लोकुर और दीपक गुप्ता की बेंच ने केंद्र सरकार से दिल्ली के गिरते भूजल की रोकथाम के लिए फौरन मध्यवर्ती और दीर्घकालीन उपाय करने को कहा है। भूजल के गिरते स्तर का एक बड़ा कारण मानव निर्मित है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली आठ मई को दिल्ली में भूजल के अत्यधिक दोहन पर चिंता जाहिर की थी। अनियोजित औद्योगिकीकरण और शहरीकरण की नीति के कारण पेड़-पौधे काटे जा रहे हैं, जिससे वष का अनुपात घटता जा रहा है। अदृग्दर्शी और बेतरतीब आधुनिक विकास के चलते हमने जोहड़ और तालाब जैसे जल संचयन के पारंपरिक स्रोतों को उपेक्षित कर दिया। हालांकि केंद्र सरकार ने भूजल प्रबंधन पर छह हजार करोड़ रुपये खर्च करने का ऐलान किया है, मगर इस तरह की सरकारी योजनाओं का क्या दृष्ट होता है, सभी जानते हैं। भूमिगत जल की समस्या से निबटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जल संचयन के उपायों के बारे में जागरूकता अभियान चलाना होगा।

सत्संग

मानवता

मानवता के लिहाज से भी जरूरी है कि इस धरती का हर प्राणी अपना पूरा जीवन जिए। यहां तक कि एक छोटे से कीड़े का भी अपना पूरा जीवन होता है। सिर्फ इसलिए कि कोई जीव आप से छोटा है, या वो आपसे अलग दिखाई देता है, उसे यहां जीने का कोई अधिकार नहीं है, केवल आप ही को जीने का अधिकार है, मनुष्यों का इस तरह से जीवन जीना बहुत ही स्थूल या अशिष्ट है। आज की मानवता मानवता से रहित है। मुझे लगता है कि जब तक इंसानियत ऊपर नहीं उठेगी, तब तक सचेतन तरीके से मानव आबादी पर नियंत्रण जैसी चीज होना मुश्किल है। इसके लिए सरकारों को नीतियां बनानी होंगी। लेकिन नीतियां ही काफी नहीं होंगी। किसी भी लोकतंत्र में सरकार ऐसी चीजों को जबरदस्ती लागू नहीं कर सकती। ऐसी चीजें केवल तभी काम कर सकती हैं कि जब समाज में इस बारे में अनिवार्य जागरूकता लाने के लिए प्रचार अभियान चलाए जाएं। लेकिन इसके लिए सरकार में जो लोग बैठे हैं, उन्हें निश्चित तौर पर इस विचार को आगे लाना होगा। इस दिशा में निजी संस्थाएं और एनजीओ बहुत थोड़ा ही योगदान सकते हैं, लेकिन इसके लिए सरकार का कदम जरूरी है। मानव आबादी पर नियंत्रण किए बिना पर्यावरण, भूमि संरक्षण और जल संरक्षण की बात करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आज समाज में विज्ञान एवं तकनीक के रूप में जिस तरह की शक्ति हमारे पास है, वह हर इंसान की अतिसक्रिय बना रही है। हम मानव गतिविधियों पर रोक नहीं लगा सकते क्योंकि इससे मानव की आकांक्षाओं पर रोक लगेगी। आप केवल मानव आबादी पर नियंत्रणकर सकते हैं। निश्चित रूप से आज पर्यावरण संरक्षण, हरित टेक्नोलॉजी जैसी चीजों की जरूरत है। हम केवल इतना ही कर सकते हैं-क्या हम संसाधनों के हिसाब से अपनी आबादी को संयोजित कर सकते हैं? अगर लोगों के जीवन में आवश्यक शिक्षा और जागरूकता लाई जाए तो यह ऐसी चीज है, जिसे हर इंसान कर सकता है। अगर यह काम कर लिया जाए तो फिर हमें और पेड़ लगाने की जरूरत नहीं होगी। यह धरती खतरे में नहीं है, बल्कि मानवता खतरे में है।

उत्पीड़न की घटनाओं

देशों में कितनी धार्मिक कट्टरता है। उस लंबे पत्र में कई उदाहरण दिए थे। लेकिन भारत के पड़ोसी देश नेपाल में जातीय उत्पीड़न की घटनाओं की खबरें नहीं आतीं, बड़ी तादाद में वहां महिलाओं को हर साल बड़ी संख्या में दुनिया भर के वेश्यालयों में धकेल दिया जाता है। वह दुनिया के सबसे गरीब देशों में एक है, दुनिया का एकमात्र हिन्दू राष्ट्र है, वहां भारत की तरह गुलामी के हालात भी नहीं पैदा हुए। मैंने राजनीतिक पार्टियों से पूछा था कि नेपाल में उत्पीड़न के सवालों को क्यों नहीं उठातीं। इस तरह मीडिया की भूमिका को लेकर दो तरह की घटनाओं की तुलना से दावा किया जा सकता है कि वह एक की तुलना में दूसरे को कितनी अहमियत देता है। मुझे कुछ दिनों पहले एक शोध पत्र मिला। इसमें कुछेक घटनाएं दलित उत्पीड़न की थीं और कुछेक वैसी थीं जिन्हें समाचार पत्रों में मुस्लिम उत्पीड़न की घटनाओं के रूप में जगह मिल रही थी। उस अध्ययन में साबित करने की कोशिश की गई थी कि दलित उत्पीड़न की घटनाओं से कहीं ज्यादा महत्व मुसलमानों के खिलाफ होने वाली उत्पीड़न की घटनाओं को मिल रहा है। ऐसा नहीं था कि अध्ययन करने वाली जो संस्था थी वह दलितों की शुभचिंतक थी। वह जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त लोगों की संस्था मानी जाती है। उसने उस वक्त इस तरह के अध्ययन को अपने राजनीतिक हितों के लिए महत्वपूर्ण समझा जबकि दलित और मुस्लिम के राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा था। शोध को सत्य की खोज नहीं मान सकते। सत्य सापेक्ष होता है। यहां जापान की चर्चित फिल्म रशोमोन (1950) की चंचा जरूरी हो जाती है। उसमें फिल्मकार ने एक ही घटना को कई तरह से प्रस्तुत किया है, और जिस भी तरह से वे घटनाएं प्रस्तुत की गईं, वे बिल्कुल सच लगती हैं। फिल्म की बुनावट इस प्रकार है कि उस घटना से जुड़ा हर पात्र अपने तरीके से उस घटना को प्रस्तुत करता है, और अपनी प्रस्तुति में खुद को छोड़कर दूसरे पात्रों को कटघरे में खड़ा करता है। यदि राजनीति में धर्म के इस्तेमाल को लेकर एक फिल्म बनाई जाए तो उसका हर किरदार अपने तरीके से अपनी राजनीति में धर्म को जरूरी मान सकता है। उसकी ऐतहासिकता प्रमाणित कर सकता हैं। भिन्नताओं के भरे समाज में वर्चस्व स्थापित करने की राजनीतिक होड़ एक धर्म की राजनीति दूसरे धर्म या धर्मों को कटघरे में खड़ा किए बिना आगे बढ नहीं सकती। लेकिन जहां धर्म की राजनीति से अलग सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोण से राजनीति होती है, तो वहां किसी भी घटना को देखने की दृष्टि भिन्न हो जाती है। हमारे

समाज में यह प्रवृति तेजी के साथ बढ़ी है कि किसी भी स्थिति को दो छोर पर खड़ा करके उसकी तुलना की जाए। जैसे सांप्रदायिक दंगे हों तो यह आंकड़ा प्रस्तुत किया जा सकता है कि भाजपा के शासनकाल में कितने सांप्रदायिक दंगे हुए और उनसे कितने ज्यादा दंगे कांग्रेस के शासनकाल में हुए यानी दंगे के कम और ज्यादा होने की वजह के रूप में शासन के तौर तरीकों को रखकर इस बहस को यह दिशा दी जा सकती है कि सांप्रदायिक दंगों के कारण क्या हैं? इनसे किसके हित पूरे होते हैं? मीडिया को दो नजरिये से कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। एक यह हो सकता है कि अपनी राजनीति के अनुकूल कैसे मीडिया में खबरों के लिए जगह बनाने का एक दबावमूलक वातावरण तैयार किया जाए। दूसरा, यह हो सकता है कि मीडिया जिन तरह की खबरों को अनदेखा करता आ रहा है, वैसी खबरों के लिए जगह बनाई जाए ताकि राजनीतिक पार्टियां आर्थिक-सामाजिक स्तर पर यथास्थितिवाद की पक्षधरता की सीमाओं से बाहर निकलने के लिए बाध्य हो। मीडिया में खबरों की जगह बनने के मसले को समझना बहुत पेचीदा काम हैं। एक तो मीडिया संस्थाओं का अपना एक आर्थिक लक्ष्य होता है, और संस्था अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए अपने प्रकाशन और प्रसारण को राजनीतिक दबाव के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करती है। दूसरा, राजनीतिक स्तर पर मीडिया में दबाव बनाने की कोशिश होती है कि वह उसके लक्ष्यों को हासिल करने में उसका साझेदार बने। दुनिया का कोई भी मीडिया संस्थान दावा नहीं कर सकता कि वह समाज के सभी वर्गों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। पूंजीवादी समाज में मीडिया आर्थिक-सामाजिक स्तर पर प्रभाव रखने वाले वर्गों के हितों में होता है। लेकिन वहां एक संघर्ष यह चलता है कि वह किस तरह के सामाजिक मुल्यों के साथ लंबे समय तक खुद को कायम रख सकता है। भारतीय समाज में मीडिया

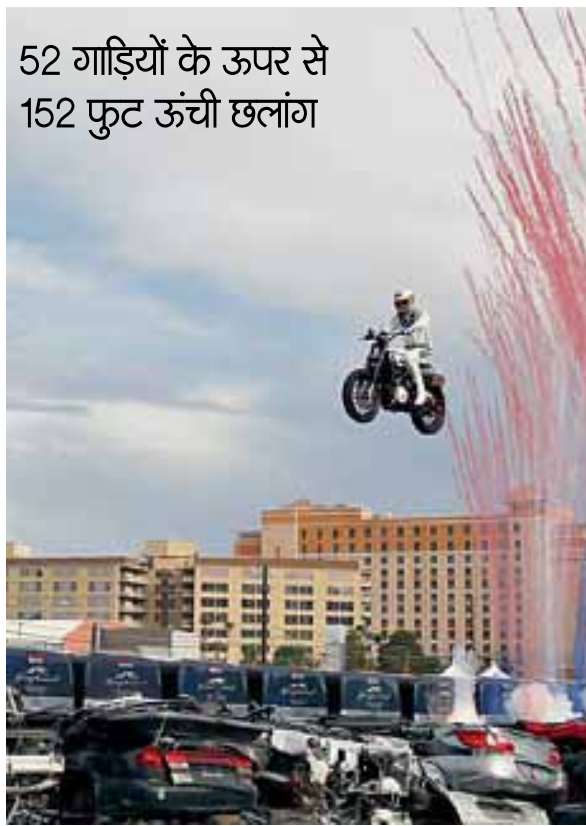
चलते चलते

दुनिया के सात अजूबों में शुमार

दुनिया के सात अजूबों में शुमार ताजमहल के संरक्षण को लेकर सर्वोच्च अदालत ने बेहद तल्लू टिप्पणी की है। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में केंद्र सरकार को कहा, ताज को संरक्षण दो या ध्वस्त कर दो। अदालत को गुस्सा एक दिन में नहीं आया है। बल्कि तीन दशकों से ताज संरक्षण के पक्ष में एक के बाद एक फैसला देने के बाद दिखा। मालूम हो कि 1993 में ताज के 500 मीटर के दायरे में आने वाले उद्योगों और श्मशान घाटों को खाली कराया गया था। मगर बेहद अफ़सोसजनक बात है कि आज भी आगरा की गिनती देश के सबसे प्रदूषित शहरों में होती है। यही नहीं ताज के आसपास कुछ उद्योगों को मंजूरी देने के विचार की भी बात सामने आई है। ताज संरक्षण को लेकर दृष्टि पत्र पेश करने

में विफल उत्तर प्रदेश सरकार को आईना दिखाते हुए अदालत कहा कि ताज के मुकाबले फ्रांस के एफ़िल टॉवर का दीदार करने 8 गुना ज्यादा लोग आते हैं। यह सरासर सरकारी उदासीनता का मामला है। नहीं तो विश्व धरोहर स्थल की यह हालत नहीं होती। तमाम चिंताओं के बावजूद सबसे बड़ी नाकामी ताज की गिरती सफेदी के कारणों का पता नहीं लग पाना भी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कोर्ट में

फोटोग्राफी...



***ट्रेविस ने किया इवेल वाला स्टंट...**अमेरिकी शहर लास वेगास में स्टंटमैन ट्रेविस पासत्राना ने इवेल नीलवेल का पॉपुलर स्टंट किया। इसी दौरान ट्रेविस ने सीजर्स पैलेस फाउंटेन के पास रखी 52 बेकार गाड़ियों के ऊपर से 152 फुट ऊंची छलांग लगाई। ऐसा स्टंट करते हुए कई साल पहले इवेल की जान जाते-जाते बची थी।*

क्रांति समय

देशों में कितनी धार्मिक कट्टरता है। उस लंबे पत्र में कई उदाहरण दिए थे। लेकिन भारत के पड़ोसी देश नेपाल में जातीय उत्पीड़न की घटनाओं की खबरें नहीं आतीं, बड़ी तादाद में वहां महिलाओं को हर साल बड़ी संख्या में दुनिया भर के वेश्यालयों में धकेल दिया जाता है। वह दुनिया के सबसे गरीब देशों में एक है, दुनिया का एकमात्र हिन्दू राष्ट्र है, वहां भारत की तरह गुलामी के हालात भी नहीं पैदा हुए। मैंने राजनीतिक पार्टियों से पूछा था कि नेपाल में उत्पीड़न के सवालों को क्यों नहीं उठातीं। इस तरह मीडिया की भूमिका को लेकर दो तरह की घटनाओं की तुलना से दावा किया जा सकता है कि वह एक की तुलना में दूसरे को कितनी अहमियत देता है। मुझे कुछ दिनों पहले एक शोध पत्र मिला।

सतीश पेडणोकर



पर सामाजिक-आर्थिक स्तर पर वर्चस्व रखने वालों की पक्षधरता को लेकर कई शोध सामने आ चुके हैं। हाल के वर्षों में मीडिया पर लगातार दबाव बना हुआ है कि संविधान के उस मूल्य को छोड़ दे जिसे धर्मनिरपेक्षता के रूप में स्थापित किया गया है। इसीलिए जब वैसी घटनाएं होती हैं, जिनका राजनीतिक स्तर पर असर होता है, तो दो घटनाओं को सामने रख दिया जाता है। मसलन, जम्मू के कटुआ में नाबालिग से रेप और हत्या की घटना और मध्य प्रदेश के मंदसौर में नाबालिग से रेप की घटना को सामने रख दिया गया क्योंकि एक के बलात्कारी को हिन्दू मान लिया गया और पीड़ित को मुसलमान; और दूसरी घटना में पीड़ित को हिन्दू और बलात्कारी को मुसलमान। सांप्रदायिक दृष्टि से दोनों घटनाओं के बीच और उनके खिलाफ प्रतिक्रियाओं की तुलना करें तो किन-किन तयों को छुपाया जा सकता है। पहला, दोनों राज्यों में शासन करने वाली राजनीतिक पार्टी एक ही है। दूसरा, रेप की संस्कृति

के विस्तार के कारणों की तरफ से ध्यान दूसरी तरफ हटाया जा सकता है। इसी तरह ईसाइयों द्वारा धर्म परिवर्तन कराने की घटनाओं को लेकर कहा जा सकता है कि मीडिया में उन्हें पर्याप्त जगह नहीं मिली। बिल्कुल यह सच लग सकता है। लेकिन ठीक उसी तरह से उसने इस सच्चाई को भी पर्याप्त जगह नहीं दी कि लाखों की संख्या में गरीब-गुरबे और आदिवासियों को दूरदराज के जंगल में जाकर पहली बार ईसाइयों ने ही स्कूल के दर्शन करवाए। डॉ. राम दयाल मुंडा ने एक किताब में आदिवासी अस्तित्व व झारखंडी अस्मिता के सवाल पर बताया है कि कैसे आदिवासियों का हिन्दूकरण किया गया है। लेकिन उसे भी पर्याप्त जगह अब भी नहीं मिलती। अपने वर्चस्व के चश्मे से देखने से सच की कई परतें दबी रह जाती हैं।

पुलिस के प्रति आमजन का अविास

ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुलिस सुधार के मसले पर नये दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकारों द्वारा की जाने वाली कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है, और राज्य पुलिस प्रमुख की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग द्वारा गठित पैनल के माध्यम से किए जाने के निर्देश दिए हैं। दूसरी तरफ़ मद्रास हाई कोर्ट ने पुलिस को साप्ताहिक अपकाश न दिए जाने पर चिंता जाहिर की है। जाहिर है कि मद्रास हाई कोर्ट द्वारा सरकार से इस बाबत सवाल पूछना और सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश पुलिस सुधार के अहम पहलू हैं। लेकिन गौर करें तो, सर्वोच्च न्यायालय के हालिया दिशा-निर्देश में कुछ भी नया नहीं है। ज्यादातर बातें प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ, 2006 मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों की पुनरावृत्ति ही हैं। लेकिन विवंडान है कि आज लगभग 11 वर्ष बीत चुके हैं, और अधिकतर राज्य सरकारें अब तक इन निर्देशों का सही से पालन नहीं कर पाई हैं। कम-से-कम दो सालों का सेवाकाल शेष होने पर भी अधिकारी को पुलिस महानिदेशक बनाने पर सुप्रीम कोर्ट का जोर पुलिस सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम था, लेकिन सेवानिवृत्ति से ठीक पहले अधिकारी को डीजीपी बना देना सियासी मंजूबे को हासिल करने के अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन अहम सवाल है कि सरकार की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? राजनीतिक हित साधना जरूरी है, या सामाजिक हित? क्योंकि, पुलिस तो समाज सेवा के लिए होती है, न कि सरकार की सेवा के लिए। मौजूदा वक्त में काम के दौरान पुलिस के सामने अनेक समस्याएं आती हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसी हैं, जो सभी राज्यों में कमोबेश एक जैसी हैं। ज्यादातर राज्यों में पुलिस की छवि मनमानी करने, पिंपल फ्रेंडली होने और अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने वाली रही है। हमेशा ऐसे किस्से सुनने-पढ़ने और देखने को मिलते हैं, जिनमें पुलिस द्वारा अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया जाता है। पुलिस का नाम लेते ही प्रताड़ना, क्रूरता, अमानवीय व्यवहार, उगाही, रिश्तत आदि जैसे शब्द दिमाग में चलने लगते हैं। इसके पीछे पुलिस में संख्या बल की भारी कमी की वजह से काम का अतिरिक्त दबाव और उनका मानसिक रूप से थका होना बड़े कारण रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक हर 450 लोगों पर एक पुलिसकर्मी होना जरूरी है जबकि भारत में औसतन 732 लोगों पर एक पुलिसकर्मी उपलब्ध होता है। सच तो यह है कि राज्य सरकारों पर कई बार पुलिस प्रशासन के दुरु पयोग के आरोप भी लगते रहे हैं। मुमकिन है कि इन्हीं सब वजहों से राज्य सरकारें पुलिस सुधार के लिए तैयार नहीं होतीं। हमें यह समझना होगा कि पुलिस सुधार को लेकर राज्य सरकारों की बेरुखी की वजह से पुलिस के प्रति आमजन का अविास और बढ़ जाता है। पुलिस में संस्थागत सुधार ही वह कुंजी है, जिससे कानून व्यवस्था को पटरी पर लाया जा सकता है। लेकिन, चिंता का विषय है कि सत्ता में आने वाली हर सरकार पुलिस के पुराने ढांचे को बनाए रखना चाहती है, ताकि वह इसे मनमाने तरीके से इस्तेमाल कर सके। सीबीआई जैसी अहम संस्था को भी राजनीतिक दखल से हम महफूज नहीं रख सके हैं लिहाजा, वक्त की जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए ताकि पुलिस-प्रशासन को राजनीति के चंगुल से निकाल कर आजादी से काम करने का मौका मिल सके। अगर ऐसा हो पाता है, तो हम समाज को कई अन्य तरह की चुनौतियों से आजाद कराने में यकीनन कामयाब हो पाएंगे।

कोडीनार, मालिया में ८ इंच से अधिक बारिश

दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र में भारी बारिश का दौर जारी



भारी बारिश के चलते राज्य के अनेक इलाके जलमग्न अगले पांच दिनों के दौरान भारी बारिश की चेतावनी

सूरत। दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के अधिकांश इलाकों में भारी बारिश जारी रही है। जिसके चलते बहुत से इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिली। कई गांवों का संपर्क अब भी टूट गया है। बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित इलाकों में भी पहुंचाया गया है। गुजरात में बारिश संबंधित अलग अलग घटनाओं में अबतक २२ लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेन्टर के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक आज सुबह पूरे हुए २४ घंटे में बहुत से इलाकों में भारी बारिश हुई है। राज्य के जिन इलाकों में अधिक

बारिश हुई हैं उनमें जामकंडोरणा में ४ इंच, मालिया में ७ इंच, सूत्रपाडा में ६ इंच, कोडीनार में आठ इंच बारिश दर्ज हुई है।

गणदेवी और चीखली में ७-७ इंच बारी हुई है। गुजरात के ८२ तहसीलों में बारिश हुई है। डांग जिले के वधई तहसील में आठ इंच से अधिक बारिश हुई है। सोमनाथ जिला के कोडीनार में ८ इंच के आसपास बारिश दर्ज हुई है। नवसारी जिले के गणदेवी में सात इंच से अधिक बारिश दर्ज हुई है। चीखली में ७ इंच से अधिक और अमरेली जिले के वाडीया में सात इंच से अधिक बारिश

हुई है। तीन तहसील में सात इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई है।

इसके अलावा भी राज्य के अलग अलग इलाकों में भी उल्लेखनिय बारिश दर्ज हुई है। जलालपुर, बगसरा, खेरगांव, धरमपुर में ६ इंच से अधिक बारिश दर्ज हुई है। पांच तहसील में पांच इंच से अधिक बारिश दर्ज हुई है। भारी बारिश के चलते लोग परेशान दिख रहे हैं। दक्षिण गुजरात और दक्षिण सौराष्ट्र के कई गांव जलमग्न दिख रहे हैं। शहर के कई इलाके और मुख्य सड़कें जलमग्न हो गई हैं। प्रशासन ने सभी कदम उठाये हैं। दक्षिण गुजरात के हालात को देखते

हुए सभी जिलों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। अगले ४८ घंटे तक दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

मौसम विभाग ने बताया है कि अलगे पांच दिनों के दौरान दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के अधिकांश इलाकों में भारी बारिश होगी।

वलसाड, दमण दादरा नगर हवेली, भरुच, नर्मदा, छोटाउदेपुर, बड़ोदा, आणंद, खेडा, पंचमहाल में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा डांग, नवसारी, तापी, सूरत में भी भारी बारिश हो सकती है। गीर सोमनाथ में भी बारिश की संभावना है। पिछले २४ घंटों में गिरनार की पहाड़ियों पर १७ इंच बारिश दर्ज की गई है।

रथयात्रा से पहले गोमतीपुर में से पिस्तोल, बम, बरामद

विस्फोटक चीजे मिलने से सनसनी फैली

पुलिस टीम ने जानकारी के आधार पर छापेमारी की

अहमदाबाद। भगवान जगन्नाथजी की रथयात्रा कल शनिवार के दिन निकलेगी तब शहर के संवेदनशील गोमतीपुर इलाके में एक बुटलेगर के घर में से आज पिस्तोल, पाइप, बम, सुतली बम मिलने से सनसनी फैल गई। केरोसीन की बोटल समेत अन्य चीजवस्तुएं भी बरामद की गई हैं। विस्फोटक मिलने से पुलिस तंत्र में भागदोड़

मच गई है। दूसरी ओर पुरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था रथयात्रा को लेकर पहले से ही मजबूत की जा चुकी है। जानकारी मिलते ही एफएसएल की टीम जांच करने के हेतु से पहुंची। विस्फोटक चीजवस्तु में पटाखे का पाउडर मिला होने की जानकारी दी गई है। पारिवारिक लड़ाई में किसी ने बुटलेगर के बारे में पुलिस को गलत जानकारी दिये जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है। मिली जानकारी के आधार पर पुलिस टीम ने गोमतीपुर इलाके में राजपुर टोलनाका के

निकट मोहंमद रफीक उर्फ गुड्डु नाम के बुटलेगर के मकान में छापेमारी की। पुलिस ने छत पर जांच करने के दौरान बम, सुतली बम, पिस्तोल और केरोसीन भरी हुई बोटल जब्त की है। गुड्डु और उसके परिवार के सदस्यों की गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस जांच में इस प्रकार की जानकारी निकलकर आई है कि गुड्डु शराब के कारोबार से जुड़ा हुआ है। उसने कुछ सालों पहले एक युवक की हत्या भी की थी। गुड्डु पहले बुटलेगर हुसैन के अड्डे पर भी काम कर चुका है।



रथयात्रा के सभी रूट का निरीक्षण पुलिस कंट्रोल रूम के द्वारा किया जाएगा। जिसमें सीसीटीवी के साथ सभी विस्तार को जोड़ा गया है।

नर्मदा बांध में पानी की सतह १०९.९५ मीटर तक पहुंचा



अहमदाबाद। मध्यप्रदेश के आसपास के इलाकों में भारी बारिश के चलते नर्मदा डेम में भी पानी की सतह में बढ़ोतरी हुई है। राजपीलला के निकट केवडियो कोलोनी में नर्मदा बांध की सतह १०९.९५ तक पहुंच चुकी है। गुजरात की लाइफ लाइन समान गीनी जानेवाली नर्मदा डेम के उपरवास के इलाकों में और मध्य प्रदेश में भारी बारिश के चलते नर्मदा डेम में पानी की नई आवक

हुई है। डेम की सतह लगातार बढ़ रही है। इन दिनों नर्मदा डेम में ९६७४ क्यूसेक पानी की आवक हुई है। जिसके चलते नर्मदा डेम की सतह अब बढ़कर १०९.९५ मीटर तक पहुंच गई है। डेम की सतह ११० मीटर तक पहुंच जाने के बाद आईडीपीटी टनेल बंध की जाएगी। इन दिनों डेम में ३५९३.७७ एमसीएम पानी का संग्रह है। आज शाम तक नर्मदा डेम की सतह ११०

मीटर तक पहुंचने की संभावना है। पिछले २४ घंटों में नर्मदा जिले में लगातार बारीश हुई है। नांदेद में २ इंच से अधिक बारिश हुई है। तिलकवाडा में ३ इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा गरुडेश्वर में ३ इंच से अधिक बारिश दर्ज हुई है। भारी बारिश के चलते नर्मदा में पानी की नई आवक हुई है और सरदार सरोवर डेम की सतह बढ़कर १०९.९५ मीटर तक पहुंच गई है। राजपीलला के निकट केवडिया कोलोनी में पानी की सतह बढ़ने को लेकर स्थानिय लोगों में उत्सुकता भी दिख रही है।



कलश व ध्वज यात्रा के साथ हुआ महायज्ञ का आरंभ

सूरत। श्री श्याम सेवा ट्रस्ट द्वारा आपाढी गुप्त नवरात्री के पावन अवसर पर आयोजित सहस्त्रचंडी नव-कुंडीय हवनत्मक महायज्ञ का आरंभ शुक्रवार को किया गया। इस अवसर पर सुबह 7 बजे से विशाल कलश एवं ध्वज यात्रा का आयोजन वी.आई. पी. रोड स्थित श्याम रचना अपार्टमेंट से किया गया। यात्रा में सैंकड़ों महिलाओं एवं पुरुष कलश एवं निशान लिए बाबा की जयकार करते हुे बैंड बाजों के साथ श्री श्याम मन्दिर पहुंचे। सुबह 10 बजे से पूजा विद्यान प्रारम्भ किया गया जिसमें मण्डप प्रवेश एवं देव-प्रतिष्ठा पूजन यजमान परिवारों द्वारा सुरेन्द्र जी महाराज एवं शुभ जी महाराज की देख रेख में किया गया। 21 जुलाई तक चलने वाले आयोजन में प्रतिदिन सुबह 8 बजे से पूजा विद्यान एवं शाम 4 पजे से हवन आरती होंगे।

भगवान जगन्नाथजी की ११७ रथयात्रा होगी

गुजरातभर में आज १६४ रथयात्रा निकाली जाएगी

सूरत। गुजरातभर में शनिवार के दिन अलग अलग जगहों पर रथयात्रा का आयोजन किया गया है। पुरे गुजरात में ३३ जिलों में रथात्रा निकाली जाएगी। रथयात्रा के अलावा शोभायात्रा का भी आयोजन किया गया है। जहां अधिक श्रद्धालु जमा होंगे वहां की रथयात्रा पर विशेष नजर रखी जाएगी।

सभी जगह पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जा चुकी है। गुजरातभर में अलग अलग इलाकों में १६४ से अधिक रथयात्रा और शोभायात्रा निकलेगी। भगवान जगन्नाथ की ११७, अन्य देवी देवताओं की ४७ समेत कुल मिलाकर १६४ रथयात्रा और शोभायात्रा निकाली जाएगी। १६ जिलों में बड़ी रथयात्रा निकाली जाएगी। १८ संवेदनशील रथयात्रा है। संवेदनशील



इलाकों में निकलने वाली रथयात्रा के संदर्भ में एसपी, डीवायएसपी स्तर के अफसरों की पसंदगी की गई है। उन्हें सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रथयात्रा देशभर में श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रतिक समान बन चुकी है। गुजरात के गृह विभाग की ओर से सुरक्षा को लेकर सभी इन्तजाम कर

दिये गए हैं। मुख्यमंत्री विजय रुपाणी के मार्गदर्शन में सभी उपाय किये गए हैं। कोई भी घटना न घटे इसके लिए भी आयोजन किया गया है। राज्य स्तर से लगातार मोनीटरिंग की व्यवस्था की गई है। भावनगर जिले में कुल ११ रथयात्रा निकलेगी। जेसमें एक आईजी, डीआईजी, १५ डीवायएसपी,

३६ पीआई, ११० पीएसआई अफसरों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी तरह आणंज जिला में १५ रथयात्रा निकलेगी जिसमें आईडी, डीआईजी, डीवायएसपी, पीआई और पीएसआई को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। राज्य में १७ एसआरएफ की कंपनी स्टेन्ड बाय पर रहेगी।



जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के लिए पास कन्वीनटर हार्दिक पटेल भी पहुंचे। महंत के आशिर्वाद भी लिये।

महादेव मीडिया

रोहताश यादव 9924144499, 7015339195

वीजिटिंग कार्ड, बिल बुक, लेटर पैड, बेनर, पोस्टर, आदि का डिजाइन बनवाने के लिए संपर्क करें। (हिन्दी, गुजराती)

हिन्दी, गुजराती न्युज पेपर डिजाइन करवाने के लिए संपर्क करें।

304 केवल कॉम्पलेक्स नवा गाम, डिंडोली, उधना सूरत।